तंबाकू कंपनियों द्वारा प्रायोजित शोध का प्रकाशन न करने का संकल्प

कई शोध पत्रिकाओं ने फैसला किया है कि वे तंबाकू कंपनियों के समर्थन से होने वाले शोध के परिणाम प्रकाशित नहीं करेंगी। ऐसी ही एक शोध पत्रिका है *प्लॉस मेडिसिन* जिसने तंबाकू कंपनियों द्वारा वित्त-पोषित अध्ययनों को न छापने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय के कारणों पर रोशनी डालते हुए *प्लॉस मेडिसिन* के संपादक जिनी बार्बोर ने बताया कि उनकी पत्रिका ने पिछले वर्ष यह तय किया था कि वे उन स्थितियों व कारकों को प्राथमिकता देंगे जो सबसे ज़्यादा बीमारियों का कारण बनते हैं। ज़ाहिर है कि तंबाकू इस तरह का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। तंबाकू दुनिया भर में प्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोगों की जान लेती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। तो तंबाकू सम्बंधी शोध कार्य का प्रकाशन *प्लॉस मेडिसिन* की प्राथमिकता बना मगर साथ ही पत्रिका यह भी नहीं चाहती थी कि तंबाकू कंपनियों द्वारा प्रायोजित शोध की बाढ़ आ जाए क्योंकि तंबाकू कंपनियां ऐसे शोध को तो समर्थन नहीं देंगी जो जन स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से किया जाएगा।

बार्बोर का यह भी मत है कि शोध पत्रिकाएं मूक प्रकाशक नहीं हो सकतीं। मानव स्वास्थ्य के हितों को बढ़ावा देना उनका दायित्व है। यदि तंबाकू कंपनी प्रायोजित शोध के प्रकाशन पर रोक लगेगी तो कई शोधकर्ता इस तरह की वित्तीय सहायता से बचने की कोशिश करेंगे।

इस तरह का निर्णय लेने वाली अन्य शोध पत्रिकाओं में *प्लॉस वन* और *प्लॉस बायोलॉजी* के अलावा *ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर* और *अमेरिकन थॉरेसिक सोसायटी जर्नल* भी शामिल हैं।

जहां पत्रिकाओं का यह फैसला स्वागत-योग्य है वहीं एक सवाल यह भी है कि नई दवाइयों के परीक्षण अक्सर दवा कंपनियों के पैसे से होते हैं। यह देखा गया है कि दवा कंपनी के पैसे से होने वाली ट्रायल (परीक्षण) में कंपनी के पक्ष में निष्कर्ष हासिल होने की संभावना सामान्य से ज़्यादा होती है। तो सवाल यह है कि सिर्फ तंबाकू को क्यों प्रतिबंध के लिए चुना जाए। इस सवाल के बारे में बार्बोर का मत है कि कंपनियों द्वारा दवाइयों के क्लीनिकल ट्रायल में समस्याएं हैं मगर दवाइयां लाभदायक भी हो सकती हैं। तंबाकू उत्पाद तो सदा हानिकारक ही होते हैं। इसलिए तंबाकू का मामला थोड़ा अलग है। ***(स्रोत फीचर्स)***